अन्य देशों के बैंकों की तुलना के भारतीय बैंकों की नान-परफारमिंग एसैस्ड्स

4501. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व के अन्य बैंकों की तुलना में भारतीय बैंकों की नान-परफारमिंग एसैस्ड्स की मात्रा बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि हांगकांग, कोरिया, ताईवान, अमरीका और जापान में नान/परफारमिंग एसैस्ट्स दिये गये कुल ऋण का क्रमश: 2,7, 0.80, 1,1 और 3.4 प्रतिशत है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के पास उपलब्ध सूचना क्या है; और

(घ) 1997-98 में भारत में बैंकों में इसकी प्रतिशतता कितनी है और इस प्रतिशतता में वृद्धि के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम,): (क) से (ग) पूर्वी एशिया संकट के बाद उपलब्ध संकेतों से पता चलता है कि पहले से उपलब्ध अनुमानों की तुलना में से कुछ देशों में काफी अधिक अनिष्पादित आंस्तियां (एनपीए) विद्यामान है। वह भी उल्लेख किया जा सकता है कि एनपीए के वर्गीकरण से संयंधित प्रक्रिया सभी देशों में समान नहीं है।

(घ) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निवल आस्तियां विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिए) एनपीए के विस्तार के लिए मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ साथ उधारकर्ता द्वारा निधियों का अन्यत्र प्रयोग, वापसी अदायगी में जानबूझ कर चूक, वित्तापोषित इकाई का आक्षण प्रबंधन, कच्चे माल की अनुर्थक्षमता का रुग्णता, मांग पैटर्म, अधिक लागत/समय का लगना, श्रमिक समस्या, प्राकृतिक आपदाएं प्रदूषण के कारण इकाई को दूसरी जगह स्थापित करना, आदि सम्मिलित है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक 31.3.1997 और 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार निवल अनुपयोग्य अस्तियों का प्रतिशत

स्टेट बैंक समूह	31.3.1997 के निवल अनुफज्योज आस्तियों का प्रतिशत	31.3.19-98 के निवल अनुफज्योज आस्तियों का प्रतिशत (-)
	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	7.30	6.05
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	7.96	7.13
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	11.42	10.88
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	11.29	9.53
स्टेट बैंक आफ मैसूर	10.96	9,36
स्टेट बैंक आफ पटियाला	5.88	7.04
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	6.47	6.57
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8.82	13.83
राष्ट्रीयकृत बैंक		
इलाहाबाद बैंक	14.84	11.38
आन्ध्रा बैंक	4.10	2.92
बैंक आफ बड़ौदा	8.94	7.52
बैंक आफ इंडिया	6.52	7.34
बैंक आफ महाराष्ट्र	9.66	8.59
केनरा बैंक	9.32	8.25
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	14.40	12.21
कार्पोरेशन बैंक	3.63	2.93
देना बैंक	9.40	8.28
इंडियन बैंक	25.24	23.71
इंडियन ओवरसीज बैंक	7.64	6.26
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	5.64	4.50

	1	2	3
	पंजाब एण्ड सिंघ बैंक	12.04	10.84
	पंजाब नेशनल बैंक	10.38	9.57
	सिंडिकेट बैंक	7.53	5.78
	यूको बैंक	13.73	11.14
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	6.98	7.66
	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	18.70	12.10
	बिजया बैंक	9.56	7.40

(*) अनंतिम।

आघारभूत सुविधाओं के लिए बांधित धनराशि

4502. **श्री बरजिन्दर सिंह**:

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, देश में आघारभूत मूल सुविधाओं के बनाने के लिए योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु अगले पांच वर्षों में वांछित धनराशि का आकलन क्या है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी वांछित धनराशि का अनुमान लगाया है; और

(ग) विद्युत, संचार, इस्पात, पैट्रोलियम, सड़कों, रेल और कोयले आदि के क्षेत्र में आवश्यकता का कुल कितना अनुमान है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 1994 में गठित आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के वाणिज्यिकरण संबंधी विशेषज्ञ दल ने जून, 1996 में सरकार को प्रस्तुत "इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट" में आघारभूत ढांचा क्षेत्रकों अकार्त विद्युत, सड़कें, पतन, दूरसंचार और शहरी आघारभूत ढांचे के लिए निदेश आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। विशेषज्ञ दल के अनुसार आघारभूत ढांचा क्षेत्र में कुल निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़कर वर्ष 2000-01 तक सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत होने की आशा है। समग्र रूप में वह वार्षिक निवेश में 600 बिलियन रू. से वर्ष 2000-01 तक लगभग 1100 बिलियन रू. की वृद्धि को इंगित करता है। इस अवधि के दौरान (1996-97 से 2000-01) किए जाने वाले कुल निवेस के रूप में अनुमान 4000-4, 500 बिलियन रू. बैठते हैं।

(ग)विशेषज्ञ समूह ने आघारभूत ढांचे के क्षेत्रवार निवेस का भी अनुमान लगाया है, ये इस प्रकार है:-

क्षेत्रक	1996-97 से 2000-01 (बिलियन रू.)
विद्युत	1834
दूर संचार	740
सड़क	320
पतन	100
शहरी आघारभूत ढांचा	800-940

सरकार द्वारा उधार लिया जाना

4503. **श्री बरजिन्दर सिंह**:

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार, जून 1998 के अन्त तक विभिन्न माध्यमों से 79,000 करोड़ रुपये उधार ले चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उधार ली हुई सही राशि क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा भारी मात्रा में उधार लेने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अवसरों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार उधार लेने की कोई सीमा निर्धारित करने का विचार करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) कुल व्यय औऱ ऋण-भिन्न प्राप्तियों (राजकोषीय घाटा) के बीच अन्तर की पूरा करने के लिए सरकार को सभी स्रोतों से आवश्यक कुल उधार राशि चालू वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में 91025 करोड़ रुपए आंकी गई है। जून अंत, 1998 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किसी भी तरह एक वर्ष की मध्यावधि के आंकड़े वर्षान्त की स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं करते।

सरकार ऋण-भिन्न प्राप्तियों को अधिक से अधिक बढ़ाकर तथा वय्य को नियंत्रित करते हुए चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे की बजटीय स्तर पर रोके रखने का प्रयास करेंगी।